



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र 1936 (श०)
(सं० पटना 744) पटना, शुक्रवार, 12 सितम्बर 2014

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 सितम्बर 2014

सं० 2ब०/मु०मं०न०वि०यो०, 08-01/2013-2726/न०वि०एवंआ०वि०—बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-75(छ) के परन्तुक में नगर निकायों को योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राशि के व्यय की सीमा निर्धारित की गई है जो निम्नवत है:-

“परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा नगर निगमों में दस लाख रु० से अधिक किन्तु पचीस लाख रु० से अनधिक, नगर परिषदों में पाँच लाख रु० से अधिक किन्तु बारह लाख रु० से अनधिक तथा नगर पंचायतों में दो लाख रु० से अधिक तथा पाँच लाख रु० से अनधिक की संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी”;

“परन्तु यह और कि यथा स्थिति नगर निगमों में पचीस लाख रु० से अधिक नगर परिषदों में बारह लाख रु० से अधिक तथा नगर पंचायतों में पाँच लाख रु० से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी”।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा-75(छ) में बिहार अधिनियम संख्या 8, 2009 द्वारा एक नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया गया है जो निम्नवत है:-

“परन्तु यह और भी कि विभाग उपर्युक्त व्यय सीमा में समय-समय पर अधिसूचना द्वारा परिवर्तन कर सकेगा”।

3. उपरोक्त कंडिका 2 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त कंडिका 1 में अंकित व्यय सीमा में निम्नवत वृद्धि की जाती है :-

“परन्तु, यह कि मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में 30 लाख से अधिक किन्तु 50 लाख रुपये से अनधिक, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 20 लाख रुपये से अधिक किन्तु 40 लाख रुपये से अनधिक, नगर परिषदों में 10 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख से अनधिक तथा नगर पंचायतों के लिए 5 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख से अनधिक संविदा प्राधिकृत स्थायी समिति की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

परन्तु यह और कि यथास्थिति 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों के लिए 50 लाख रुपये से अधिक, 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगमों में 40 लाख रुपये से अधिक, नगर परिषदों में 20 लाख रुपये से अधिक तथा नगर पंचायतों में 10 लाख रुपये से अधिक के व्यय की कोई संविदा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं की जा सकेगी।

4. विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूर्व की स्वीकृत योजनाओं पर यह लागू नहीं होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

जय प्रकाश मंडल,

सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 744-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>